RAJYA SABHA

Wednesday, The 9th April, 2003/19 Chaitra, 1925 (Saka)

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सभापति: Q. NO. 381, श्री दारा सिंह चौहान।

रमा शंकर कौशिक: श्रीमान् वह नहीं हैं, उन्होंने अथोराइज़ किया है।

सभापति: तो मैं आखिर में लूंगा।

B1. *[The questioner (Shri Dara Singh Chauhan) was absent. For
ır vide page 32 infra.]*

Special package for development of J&K

2. SHRI T.S. BAJWA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be
ed to state:

whether Government have announced any special package for
opment of Jammu and Kashmir;

) if so, the details thereof; and

:) the amount spent on different sectors during the year 2002-03?

HE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
I HARIN PATHAK): (a) to (c) A Statement is laid on the table of the
e.

Statement

a) and (b) The Prime Minister during his visit to Jammu & Kashmir
3.5.2002 had announced a package for "employment, rail and road
lopment, relief & Security" for J&K to be implemented over a period
to 10 years. The main development related schemes/projects
red in the package comprise railways, roads, development of
es, Agri-export zones for apples and walnuts, development of
culture, eco-restoration of degraded catchment areas of Chenab and
ım, Border Area Development Programme etc.

In addition, Department of Industrial Policy and Promotion have in June, 2002 notified a "New Industrial Policy and other concessions for the State of J&K" which comprises incentives like capital investment subsidy, interest subsidy, insurance premium, income tax exemption etc.

(c) The above mentioned schemes and projects are being implemented by various concerned Ministries/Departments. As informed by the concerned Ministries/Deptts., a sum of approximately Rs. 346.75 crore have been released so far during the year 2002-03 towards implementation of the package which includes Rs. 236.45 crore for Railways, Rs. 4.06 crores for roads, Rs. 2.9 crores for development of traditional cottage industries, Rs. 100 crores for Border Area Development Programme and Rs. 3.32 crores for eco-restoration of degraded catchments of Chenab, Jhelum and Shivaliks.

श्री टी. एस. बाजवा: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए क्या सरकार ने कोई स्पेशल पैकेज की घोषणा की है? यदि की है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्री हरिन पाठक: माननीय सभापति जी, प्रधान मंत्री जी जब 23 मई, 2002 को जम्मू-कश्मीर के तीन दिन के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने वहां स्पेशल पैकेज फॉर डवलपमेंट ऑफ जम्मू-कश्मीर की घोषणा की थी। उस घोषणा के अंतर्गत उन्होंने पांच और दस साल की अवधि के बीच पूरे जम्मू-कश्मीर में 6423.84 करोड़ रुपए की एक योजना विभिन्न मंत्रालयों के जरिए, जैसे रोड डवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज, एग्रीकल्चर वगैरा के लिए अलग-अलग मंत्रालयों को लेकर सारी योजना की घोषणा की जिस में विभिन्न मंत्रालयों के जरिए डवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट की स्कीम 6229.84 करोड़ की है, सेक्यूरिटी रिलेटेड स्कीम 56 करोड़ की है, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन स्कीम 138 करोड़ की है। इस तरह अलग-अलग मंत्रालयों के जरिए इस दस साल की अवधि में 2013 तक-प्रधान मंत्री जी की यह भी मंशा है कि यह अवधि भले ही 2013 की हो मगर जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी यहां से वहां यह पैसा दिया जाए और पूरे जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण विकास किया जाए।

श्री टी.एस. बाजवा: महोदय, मंत्री जी ने कहा कि बॉर्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम के लिए सौ करोड़ रखा गया है, यह स्कीम तो इस से पहले भी चलती थी तो जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए स्पेशल पैकेज के जरिए कौन सी नई स्कीम रखी गयी, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। ये जो स्कीम्स इन्होंने बताईं, ये इस से पहले भी चलती थीं।

श्री सभापति: इस में धनराशि ज्यादा कर दी गयी है।

श्री टी. एस. बाजवा: सर, इस में बॉर्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जो सौ करोड़ रुपया रखा गया है, वह पंजाब से शुरू होकर कारगिल तक जाता है। इस में 4 करोड़ रुपया सड़कों के लिए रखा है, तो इस में स्पेशल पैकेज क्या हुआ? यह तो पहले भी था।

श्री हरिन पाठक: सर, यह जो कह रहे हैं, वह रुटीन डवलपमेंट योजना के संदर्भ में है। जहां तक प्रधान मंत्री जी की योजना है, उस योजना के अंतर्गत रेलवे मंत्रालय की ओर से करीब 3600 करोड़ की योजना है...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप एक मिनिट बैठिए।

श्री हरिन पाठक: सर, आप जो कह रहे हैं, वह रुटीन पंचवर्षीय योजना के फिगर्स बता रहे हैं। मैं प्रधान मंत्री जी के स्पेशल पैकेज की बात कर रहा हूं। उस में सर्फेस ट्रांसपोर्ट के लिए 1335 करोड़ की योजना है, इस में टैक्सटाइल के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के लिए है, प्लानिंग कमीशन के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए है। इस में वहां की पूरी सीमाएं हैं और उन सीमाओं के मॉडर्नाइजेशन के लिए भी 56 करोड़ रुपए की योजना घोषित की गयी है। तो यह जो सारी रकम है, यह सभापति जी जैसा कि आप ने कहा, इन योजनाओं में राशि बढ़ा दी गयी है। इस में रुटीन पैसा जो केन्द्र सरकार की ओर से राज्य को जाता है, सह बाकी राज्यों में...(व्यवधान)... 70 परसेंट लोन होता है और 30 परसेंट ग्रांट होती है, मगर चूंकि जम्मू-कश्मीर को स्पेशल स्टेट्स दिया है, उन को 90 परसेंट ग्रांट 10 परसेंट लोन दिया जाता है। तो यह सारी रकम बढ़ा दी गयी है।

DR. MANMOHAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, I think all sections of the House will agree that Jammu and Kashmir is facing special problems of reconstruction and development. The Prime Minister had announced a scheme in May, 2002. Since then much water has flowed down the river Jhelum. Now, we have a new Government there. I think it is necessary to take a holistic view of the reconstruction and development requirements of the State of Jammu and Kashmir. In this context, I would like to ask the hon. Minister: Would the Government consider the establishment of a separate Cabinet Committee to look into the reconstruction and development needs of Jammu and Kashmir, backed by a high-powered committee of officials so that they can take an integrated view of the problems of reconstruction, development and, in particular, the acute problem of unemployment among the educated youth of the State?

THE DEPUTY PRIME MINISTER, INCHARGE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI L.K. ADVANI): Mr. Chairman, Sir, I fully agree with the observations of the Leader of the Opposition and I can only say that after the coming into office of the new Government, the interaction between the Centre and the State has continued very intensely. Of course, there had been special meeting in respect of the security, but even in respect of development, nothing will be lacking.

So far as setting up a Cabinet Sub-Committee is concerned, it is a suggestion for action. But I can assure that House that continuous monitoring is done in respect of developmental projects and the amount sanctioned under the Prime Minister's special package to see how it is utilised. The State Government would always be free to approach the Central Government to see that the development works are not halted in any manner.

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, it is a matter of some satisfaction that special provisions are being made for the development of Jammu and Kashmir. Particularly, I would like to ask the Minister: What is being done about the immense hydro-electric potential of that State? It is strange that despite having all these rivers, there is also electricity shortage, power shortage in Jammu and Kashmir. Salal is getting silted up. Dhool hasti and Bagliar are not yet complete. How is it after all these years, with so much investment, we still have not been able to produce massive surplus electricity in Jammu and Kashmir? Will the hon. Minister tell us whether this aspect is receiving special attention?

SHRI HARIN PATHAK: Sir, it is a good suggestion regarding the schemes, which have been announced by the hon. Prime Minister. Sir, the first part of the question put by the hon. Member is about the technological missions on horticulture. (*Interruptions*) I am coming to electricity. We have already earmarked about Rs. 100 crores for that. Specially, for electricity, if any suggestion, demand or request comes from the State Government—in this package, which is for seven ministries, it has not been incorporated—as far as any particular project is concerned, definitely, the Government will look into it.

DR. KARAN SINGH: Sir, it is not a question of new requests. These projects have been on the anvil for many years, for decades. In fact Salal project was planned in my father's time. It is not a new request that is required. These are ongoing projects. Perhaps, the Minister may enquire from the concerned Ministry and let us know.

SHRI HARIN PATHAK: Sir, whatever the pending projects are there, we will pursue them.

आतंकवादी गुट द्वारा आतंकवादी हमलों की धमकी

*383. **श्रीमती सविता शारदा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ''लश्कर-ए-तैय्यबा'' नामक आतंकवादी गुट ने भारत में बड़े पैमाने पर नये सिरे से अनेक आतंकवादी हमले करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस धमकी का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) ''लश्कर-ए-तैय्यबा'' और जैश-ए-मोहम्मद जैसे अन्य पाक इस्लामिक ग्रुप जम्मू और कश्मीर में व्यक्ति विशेषों, प्रतिष्ठानों और संस्थानों को निशाना बना रहे हैं और इन्हाने हाल के वर्षों में भारत के अन्दरूनी भागों में अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है।

(ग) आतंकवाद के खतरे से मुकाबला करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें सीमा को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, सुसमन्वित आसूचना आधारित कार्रवाईयों का प्रबोधन करना, राज्य पुलिस बलों और केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों का आधुनिकीकरण करना और सीमापार अपराध और आतंकवाद को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय/द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना शामिल है।

केन्द्र सरकार आतंकवादी ग्रुपों की गतिविधियों के कारण उत्पन्न खतरे की आशंका के बारे में समय-समय पर राज्य सरकारों को सचेत करती रहती है।